1 OCT 6 2026.qxd 30-09-2026 19:24 Page 1

यह भी नरसंहार

सर्वोच्च न्यायालयने निजी अस्पतालोंकी कार्यशैलीको कटघरेमें खड़ा करते हुए मंगलवारको जो सख्त टिप्पणी की है, वह गम्भीर विचारणीय विषय है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहताकी पीठका यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि देशभरमें निजी अस्पताल मरीजोंकी सेवा करनेके बजाय मुनाफा कमाने वाले उद्योगकी भांति काम करते हैं। शीर्ष न्यायालयने कैंसर सहित अन्य जीवनरक्षक दवाओंपर खुदरा विक्रेता मूल्य (पीटीआर) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में भारी अन्तरपर भी सवाल खड़ा किया है। अस्पतालोंकी ओरसे कैंसरकी दवाओंपर दस गुना कीमत लेनेपर चिन्ता जतायी गयी है और कहा गया है कि यह 'नरसंहार' जैसा बर्बर कार्य है और इसपर लगाम लगानेकी आवश्यकता है। कैंसरकी एक दवाकी आपूर्ति मूल्य २७०० रुपये है जिसे अस्पतालकी फार्मेसीसे २७ हजार रुपयेमें बेचा जाता है। न्यायमूर्ति मेहताने यहांतक कहा कि कारपोरेट अस्पताल किसीको भी नहीं छोड़ते हैं। वह मरीजके शवको तबतक बाहर ले जानेकी अनुमति नहीं देते जबतक उसका पूरा भुगतान नहीं हो जाता है। पीठने यह भी सुझाव दिया कि दवाके खुदरा विक्रेता मूल्यसे अधिकतम खुदरा मूल्य १६ प्रतिशतसे अधिक नहीं रखनेका एक सामान्य नियम क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालयकी टिप्पणीने देशकी निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाके उस पक्षको फिर बहसके केन्द्रमें ला दिया है, जिसे मरीज और उनके परिजन लम्बे समयसे महसूस कर रहे हैं। यह बीमारीकी मजबूरीका आर्थिक लाभमें बदल जानेकी घातक प्रवृत्ति है। मरीजोंको अस्पतालकी अपनी फार्मेसीसे दवा खरीदनेके लिए बाध्य किया जाता है, जो चिन्ताकी बात है। जहांतक कैंसरके उपचारकी बात है, वह सामान्य चिकित्सासे अलग है। लम्बे समयतक उपचार होता है और महंगी दवाएं, जांच और कीमोथैरेपीका क्रम भी चलता है। पीड़ित परिवारोंपर काफी आर्थिक बोझ पड़ता है। एक सवाल यह भी है कि सभी निजी अस्पतालोंको एक नजरसे देखना उचित नहीं है। निजी अस्पतालोंकी अपनी लागतें भी होती हैं। इसलिए मूल्य नियमन बनाते समय लागत और उचित परिचालन मार्जिनका भी ध्यान रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालयकी टिप्पणीका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने स्वास्थ्य सेवाको केवल बाजारकी वस्तु मानकर छोड़ देनेके बजाय उसे मानवीय गरिमा और सार्वजनिक हितसे जोड़कर देखनेका मजबूत संकेत दिया है। केन्द्र सरकारको भी इस दिशामें व्यावहारिक और ठोस हस्तक्षेप करनेकी जरूरत है।

कुंठित मानसिकता

जम्मू-कश्मीरके कठुआमें सीआईएसएफ जवानकी अपने ही चार सार्थी जवानोंकी गोली मारकर की गयी हत्याकी हतप्रभ करने वाली घटना अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियोंके अनुसार एक हेड-कांस्टेबलने मंगलवार शामको आपसी कहासुनीमें अपने ही साथियोंपर अंधाधुन्ध गोलियां चला दी, जिसमें एक सहायक कमण्डेट और सब-इंस्पेक्टर समेत चार जवानोंकी मौत हो गयी। घटनाके पीछे क्या कारण रहा इसकी तत्काल जानकारी नहीं हो सकी लेकिन माना जा रहा है कि हमलावर हेड-कांस्टेबलकी पत्नी भी सीआईएसएफमें कांस्टेबल है, जो अक्सर बच्चेके साथ क्वाटर गार्ड आ जाती थी, जबकि यूनिट प्रशासनसे इसकी अनुमति नहीं थी। शायद इसी बातपर विवाद बढ़ा और यह अप्रत्याशित घटना हुई। सचाई चाहे जो भी हो यह तो जांचके बाद सामने आयगा वैसे सीआईएसएफ मुख्यालयने घटनाकी जांचके लिए कोर्ट आफ इंक्वायरीका आदेश दिया है। घटनाको अंजाम देने वाले जवानको गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन इस तरहकी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ड्यूटीपर तैनात जवानोंमें सद्भाव और आपसी सौहार्दकी भावना होती है, जो एक-दूसरेकी रक्षामें अपनी जानतक गंवा देते हैं। ऐसेमें इस तरहकी हृदयविदारक घटना कई अनुत्तरित सवाल खड़े करता है। जवानोंके मन:स्थितिकी विज्ञानको समझना होगा कि जवानोंकी मानसिकता कैसी है। ऐसी घटनाके मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सैन्य अस्पतालोंमें एक मनोचिकित्सककी भी नियुक्ति होनी चाहिए और समय-समयपर जवानोंकी मन:स्थितिकी जांच भी होनी चाहिए, ताकि जवानोंकी मानसिक स्थितिका सही आकलन किया जा सके और परिस्थितिजन्य उपचार उपलब्ध कराया जा सके। सरकारको इस घटनासे सबक लेते हुए इसपर गम्भीरतासे विचार करना होगा, ताकि इस तरहकी घटनाकी पुनरावृत्ति न हो।

लोक संवाद

पैरोंके दर्दको न करें नजरअंदाज

महोदय,-सुबह उठकर जमीनपर पैर रखते ही एड़ी या पैरके जोड़में तेज चुभन महसूस होना काफी परेशान करने वाला हो सकता है। कई बार यह दर्द कुछ देर बाद कम हो जाता है, लेकिन यदि बार-बार ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर जब इसके साथ जोड़में सूजन, लालिमा या तेज दर्द भी हो। शरीरमें यूरिक एसिडका स्तर बढ़ना और उससे होने वाला गाउट इसका एक कारण हो सकता है। हालांकि सुबह एड़ीमें दर्द होनेकी वजह सिर्फ यूरिक एसिड ही नहीं होती, इसलिए सही कारण जाननेके लिए डाक्टरसे जांच जरूरी है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगके मुताबिक गाउट गठियाका एक प्रकार है, जो शरीरमें यूरिक एसिड बढ़नेपर हो सकता है। यूरिक एसिडकी मात्रा ज्यादा होनेपर इसके क्रिस्टल जोड़ोंके आसपास जमा हो सकते हैं। शरीर इन क्रिस्टलके खिलाफ प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण जोड़में अचानक तेज दर्द, सूजन, लालिमा और गर्माहट महसूस हो सकती है। गाउटका दर्द अक्सर पैरके अंगूठेके जोड़में देखा जाता है, लेकिन यह पैरों, टखने और दूसरे जोड़ोंको भी प्रभावित कर सकता है। अतः ऐसी समस्या होनेपर तुरन्त अपने चिकित्सकसे परामर्श करें। **-मोनिका शर्मा, वाया ईमेल।**

वैश्विक समस्या बनती मुफ्तखोरी

भारतमें मुफ्तखोरी योजनाएं, पिछले लम्बे समयसे आम बात हो चुकी हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रासे आगे बढ़ते हुए अब बात साइकिल, स्कूटी, मंगलसूत्र, लैपटाप और टेबतक पहुंच चुकी है। राजनीतिक दल, जो पहले सैद्धांतिक रूपसे फ्रीबीजका विरोध करते थे, वे भी ऐसी योजनाओंकी घोषणाएं कर रहे हैं।

❐ **प्रोफेसर अश्विनी महाजन**

भारतमें मुफ्तखोरी योजनाएं, जिन्हें फ्रीबीज भी कहा जाता है, को जन कल्याणके नामपर अनेक प्रकारसे औचित्यपूर्ण भी ठहराया जाता है। इसी प्रकारकी फ्रीबीजकी घोषणाएं कुछ अन्य देशोंमें भी देखने और सुननेको मिलने लगी हैं। कुछ दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सभी व्यस्क लोगोंको पांच हजार डालर देनेकी पेशकश की गयी है, जिसमें शर्त यह है कि राष्ट्रपति ट्रम्पकी रिपब्लिकन पार्टीको अमेरिकी संसद यानी हाउस और सेनेटमें जीत हासिल हो। यानी अमेरिकामें मध्यावधि चुनावोंके मद्देनजर अमेरिकी मतदाताओंको सीधे तौरपर यह पेशकश है कि आप ट्रम्पकी पार्टीको वोट दीजिए और आपको पांच हजार डालर दिये जायंगे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकासे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे जुड़ी विभिन्न एजेंसियां भारतके प्रजातंत्रके बारेमें टिप्पणियां तो करती ही हैं, भारतीय प्रजातंत्रमें शांतिपूर्ण चुनाव एवं सत्ता हस्तांतरण, प्रेस, मीडिया और बोलनेकी स्वतंत्रता, स्वायत्त न्याय पालिका एवं अन्य संस्थाओंके बावजूद भारतीय प्रजातंत्रको अत्यंत निचले स्तरपर रेटिंग की जाती है। हालांकि पिछले कुछ समयसे ये एजेंसियां अमेरिकी प्रजातंत्रकी भी रेटिंग गिरा रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौरपर वोटके बदले नोट देनेकी पेशकश, दुनियामें एक नयी बहसको जन्म दे रही है कि क्या अब विकास, स्वच्छ प्रशासन, संवैधानिक अधिकारोंकी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आमजनके लिए सुविधाओंकी बजाय फ्रीबीजके आधारपर प्रजातंत्रमें मतदाता वोट डाला करेंगे। ऐसेमें यदि सत्ता पानेके लिए राजनीतिक दल वोटरोंको राशि देनेकी पेशकश करनेमें प्रतिस्पर्धा करने लगे तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा।

यानी यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी घोषणाके बाद डेमोक्रेट पार्टी इस राशिसे ज्यादाकी पेशकश कर दे तो क्या होगा। यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यहां रुकने वाली नहीं है, यह नीचे राज्योंतक जायगी और वहां गवर्नरकी रेसमें लगे दल भी इसी प्रकारकी पेशकश करने लगे तो उसका असर जन-सेवाओंपर कितना पड़ सकता है, इसका अंदाजा भारतमें इस प्रतिस्पर्धासे लगाया जा सकता है। भारतमें मुफ्तखोरी योजनाओंकी शुरुआत कहांसे हुई, उसके बारेमें चर्चा करते हुए यदि हम उसके प्रकार और फैलावके बारेमें देखते हैं तो ध्यानमें आता है कि सरकारी खजानेपर इसका सर्वाधिक असर पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्योंमें ज्यादा दिखाई देता है। भारतके महालेखाकार और अकेंक्षक (कैग) के अनुसार २०२४-२५ में पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडुमें कुल सरकारी खर्चके १३.५ प्रतिशतसे ज्यादा इस प्रकारकी योजनाओंमें खर्च हो रहा था। हालांकि तमिलनाडु और दिल्ली इन मुफ्तखोरी योजनाओंके खासे चर्चित उदाहरण रहे हैं, लेकिन इन राज्योंमें सरकारी कर्ज सरकारी खातोंमें दिखाई नहीं देता, लेकिन यह इसलिए है कि दिल्लीमें प्रति व्यक्ति सरकारी राजस्व, राष्ट्रीय औसतके दुगनेसे भी अधिक है। इसका अप्रत्यक्ष कारण यह है कि दिल्लीकी प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसतके मुकाबले दुगनीसे भी अधिक है। कमोबेश यही स्थिति तमिलनाडुकी भी है। भारतीय जनता पार्टी इन मुफ्तखोरी योजनाओंका सैद्धांतिक रूपसे विरोध करती रही है। लेकिन अन्य राजनीतिक दलोंकी मुफ्तखोरी योजनाओंके मद्देनजर अब यह पार्टी भी सत्ताके समीकरण अपने पक्षमें करने हेतु खुलकर इन मुफ्तखोरी योजनाओंकी केवल घोषणा ही नहीं कर रही, बल्कि उनके फायदे भी गिना रही है। उदाहरणके लिए मध्य प्रदेशमें लाडली बहन योजना, दिल्लीमें मुख्य मंत्री महिला सम्मान योजना और कई अन्य राज्योंमें इस प्रकारकी योजनाएं चल रही हैं। हालांकि दिल्लीकी महिलाओंके लिए दी जाने वाली राशि केवल इसके लिए पात्र (गरीब) महिलाओंको ही मिलेगी। दिल्लीमें भारतीय जनता पार्टीने आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा रही मुफ्त बिजली, पानी आदिकी सुविधाको बरकरार भी रखा है।



भारतमें मुफ्तखोरीकी स्कीमोंके कारण राज्य कर्जके बोझ तले दब रहे हैं और उससे वे अपने नागरिकोंके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानेमें असमर्थ हैं। अब अमेरिका भी इसकी चपेटमें आ गया है। गौरतलब है कि अमेरिकामें पहलेसे ही कर्जका बोझ बढ़ता ही जा रहा है, अमेरिकामें २०१०-११ में कर्जका बोझ उनकी जीडीपीका ९५.७ प्रतिशत था, जो २०२५ में बढ़ता हुआ, १२३.९ प्रतिशततक हो चुका है। चूंकि अमेरिकाका जीडीपी सर्वाधिक है इसलिए उसकी सेहतपर इसका असर शीघ्र देखनेको नहीं मिलेगा। हालांकि आईएमएफका कहना है कि अमेरिकापर सरकारी कर्जका बोझ २०३० तक उसकी जीडीपीके १४१.५ प्रतिशततक पहुंच जायेगा।

इन सभी मुफ्तखोरी योजनाओंका असर देशपर बढ़ते कर्जके रूपमें भी दिखाई देता है। गौरतलब है कि २०१०-११ में देशपर सम्मिलित कर्ज केन्द्र और राज्य जीडीपीका ६५.६ प्रतिशत था, जिसमें केन्द्र सरकारका कर्ज जीडीपीका ४८.५८ प्रतिशत और राज्योंका कर्ज जीडीपीका २३.५ प्रतिशत था। गौरतलब है कि देशपर सम्मिलित कर्ज आकलित करनेके लिए केन्द्र और राज्योंके आपसी लेन-देनको समायोजित किया गया है। २०२४-२५ में यह कर्ज बढ़कर जीडीपीके ८१.९ प्रतिशततक पहुंच गया। जहां केन्द्र सरकारका कर्ज ४८.८ प्रतिशतसे बढ़कर ५७.५ प्रतिशततक पहुंचा, राज्य सरकारोंपर कर्ज २३.५ प्रतिशतसे बढ़ता हुआ २८.५ प्रतिशततक पहुंच गया। जिन राज्यों द्वारा मुफ्त खोरीकी योजनाओंको ज्यादा अपनाया गया है उन राज्योंका कर्ज राष्ट्रीय औसतसे कहीं अधिक है। २०२४-२५ में कई राज्योंपर उनके जीएसडीपी (राज्य की जीडीपी) के मुकाबले काफी ज्यादा कर्ज था, पंजाबमें यह ४७.३ प्रतिशत, हिमाचल प्रदेशमें ४४.० प्रतिशत, पश्चिम बंगालमें ३८.० प्रतिशत, केरलमें ३७.० प्रतिशत, राजस्थानमें ३६.० प्रतिशत और आंध्र प्रदेशमें ३४.७ प्रतिशत। कर्जका इतना ज्यादा बोझ राजकोषीय गुंजाइशको सीमित करता है, ब्याजका बोझ बढ़ाता है और उत्पादक सार्वजनिक निवेशको रोक सकता है। आमदनीसे ज्यादा खर्च और तदनुसार घाटेके बजटोंने देशपर कर्ज बढ़ाया ही है, लेकिन हालमें मुफ्तखोरीकी योजनाओंके चलते यह गति और तेजीसे बढ़ी है।

गौरतलब है कि २०१०-११ और २०१८-१९ के बीच देशपर कुल कर्ज ६३.६ प्रतिशतसे मामूली-सा बढ़कर ६६.५ प्रतिशततक ही हुआ था। लेकिन पिछले मात्र छह वर्षोंमें यह २०२४-२५ तक बढ़कर जीडीपीके ८१.९ प्रतिशततक पहुंच जाना वास्तवमें चिन्ताका विषय है। यह भी सही है कि केन्द्र सरकारकी देनदारीमें बड़ी वृद्धि कोरोना कालमें हुई थी, जब २०१९-२० और २०२०-२१ के दौरान केन्द्र सरकारकी देनदारियां जीडीपीके ६२.९ प्रतिशत और राज्य सरकारोंकी देनदारियां ३१.१ प्रतिशततक पहुंच गयी और दोनोंकी सम्मिलित देनदारियां ८८.७ प्रतिशततक पहुंच गयी। हालांकि उसके बाद सम्मिलित लेनदारिया ८१.९ प्रतिशत तक घट गयी है, जिनमें केन्द्रकी देनदारियां ५७.१ प्रतिशत हैं और राज्योंपर अब भी ये २८.५ प्रतिशत बनी हुई हैं। ध्यातव्य है कि लेकिन अब भी यह २०१०-११ के ६५.६ प्रतिशतसे कहीं अधिक हैं। समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं मुफ्तखोरीकी स्कीमोंके कारण राज्योंपर कर्जका बोझ बढ़ रहा है, जिसके चलते देशपर कुल कर्जका बोझ बढ़ा है।

कुछ लोगोंका कहना है कि मुफ्तखोरीकी यह स्कीम, जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्पने सभी वोटरोंको वायदा किया है यदि वे उन्हें सीनेट और हाउसमें विजय दिला दें तो वे हर मतदाताको ५००० अमेरिकी डालर देंगे। भारतका उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे भारतके राज्योंमें मुफ्तखोरीकी स्कीमोंके कारण वे कर्जके बोझ तले दब रहे हैं और उसकी वजहसे वे अपने नागरिकोंके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानेमें असमर्थ हैं। गौरतलब है कि अमेरिकामें पहलेसे ही कर्जका बोझ बढ़ता ही जा रहा है अमेरिकामें २०१०-११ में कर्जका बोझ उनकी जीडीपीका ९५.७ प्रतिशत था, जो २०२५ में बढ़ता हुआ, १२३.९ प्रतिशततक हो चुका है। आईएमएफका कहना है कि अमेरिकापर सरकारी कर्जका बोझ २०३० तक उसकी जीडीपीके १४१.५ प्रतिशततक पहुंच जायगा।

पृथ्वीकी रक्षाके लिए शाकाहार जरूरी

एक अक्तूबरको शाकाहार दिवसके रूपमें मनाया जाता है। यह सीधे हमारे आहारसे जुड़ा है। जो हमें हर जीवके प्रति संवेदना रखनेके लिए प्रेरित करती है। जो धरतीकी सुरक्षा, अहिंसा, प्रेम और पवित्रताको सुनिश्चित करती है ।

❐ **शकुन्तला देवी**

संस्कृतिका ताल्लुक आहारसे और आहारका ताल्लुक संस्कृतिसे है। जिन संस्कृतियोंमें हिंसा, अन्याय, शोषण और मनमाना बर्ताव होता है वहां रोजमर्राकी जिन्दगीमें हत्या और क्रूरतासे हासिल आहार यानी मांसाहारको खूब पसन्द किया जाता है। देखा जाय तो यह संवेदनाका सवाल है। हम अपनी पीड़ा और दुखको ही यदि पीड़ा और दुख समझते हैं तो किसीके साथ हमारा व्यवहार यथायोग्य हो नहीं सकता। लेकिन दुनियामें लाखोंकी तादादमें ऐसे लोग भी हैं जो हत्या, क्रूरता और मनमाने बर्तावको गैर-इंसानी बर्ताव मानते हैं। धरतीके हर जीवकी पीड़ा, दुख और परेशानीको अपनी जैसी पीड़ा, दुख और परेशानी मानने वाले ऐसे भी लाखों इंसान हैं जो किसी भी जीवकी हत्या करना हत्यामें शामिल होना या हत्याके लिए प्रोत्साहित करनेको गैर-इंसानी कवायद मानते हैं। इसी दुनियामें एक ऐसी भी दुनिया है जो जीवोंके प्रति क्रूरता, हिंसा और मनमाने बर्तावके खिलाफ रही है। ऐसे मानव मूल्योंके धनी लोगोंने १८४७ में इग्लैंडमें पहली बार शाकाहारी सोसायटीकी स्थापना की। स्थापनाके बाद संस्था दुनियाको शाकाहारके हैरान करने वाले फायदों और दुनियाको बेहतर कलके निर्माणके मद्देनजर आगे बढ़ना शुरू किया। इस मानवीय कार्यमें जर्मनी, नीदरलैंड और पश्चिमी दुनियाके दूसरे देशोंमें रहने वाले शाकाहारके समर्थकोंने इसका अनुशरण किया और इसे आगे बढ़ानेके लिए पूरी ताकत झोंक दीं। इसका असर यह हुआ हुआ कि राष्ट्रीय सोसायटियोंका एक संघ एक अन्तरराष्ट्रीय शाकाहारी संघमें स्थापित किया गया, जो आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय शाकाहार महासंघके जरिये १ अक्तूबर १९७८ को समाजमें करुणा, खुशहाली, प्रसन्नता, न्याय और शाकाहार जीवनकी संभावनाओंको बढ़ावा देनेके लिए दुनियाभरमें विश्व शाकाहार दिवस मनानेकी घोषणा की गयी। तबसे दुनियाभरमें १ अक्तूबरको विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। यह पश्चिमी दुनियामें शायद पहली बार था जहां शत-प्रतिशत मांसाहारकी जीवनशैली थी, की जगह पवित्र और हिंसारहित शाकाहारी शैलीको जिन्दगीका हिस्सा बनानेके लिए इतने बड़े पैमानेपर कार्य करना शुरू किया गया। आज दुनियाके सभी विकसित देशोंमें शाकाहारियोंकी एक अच्छी खासी तादाद है।

शाकाहार दिवस मनानेका एक बेहद खास मकसद है। वैज्ञानिकोंके जरिये प्रमाणित शाकाहारके फायदों, शाकाहारकी खूबियों, मांस, मछलीकी अपेक्षा सहज उपलब्धता, हिंसामुक्त समाज बनाने, जीव-जन्तुओंको विलुप्त होनेसे बचाने, पर्यावरणके लिए पूरी तरह अनुकूलताएं शांति, सुख, जीवोंके प्रति सदभावना पैदा करने, मानवीय क्रूरताओंसे निजात पाने, वातावरणमें हिंसक या नकारात्मक तरंगोंको रोकने, मांसाहारसे बढ़ रही बीमारियोंके फैलावको रोकने और जगत्में आहारके नामपर तरह-तरहकी क्रूरताओं और हिंसक कवायदोंसे छुटकारा पानेके लिए लोगोंको जागरूक करने जैसे तमाम वजहोंसे विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है शाकाहार ही क्यों। मांसाहार क्यों नहीं, हर व्यक्तिका मौलिक अधिकार है कि जो चाहे, जब चाहे, वह खाये और पिये। सामान्य तौरपर यह बात वाजिब लगती है, लेकिन हम विचार करें तो इन दोनों सवालोंमें उसका जवाब भी है। शाकाहार शब्द संस्कृतका है। इसमें पहला शब्द 'शाक' है जिसका मायने शांति होता है 'का' मायने क्रान्ति है। हा, मतलब 'हार्द' यानी स्नेह, प्रेम और सुकुमारता। और 'र' का मायने है रक्षा। शाकाहार शब्दके सभी अक्षरोंके मायने समझ लेनेपर शाकाहारकी बेहतर समझ हो जाती है। शाकाहारको शांति, क्रांति, हार्द और रक्षा या रसाके संदर्भमें देखनेकी जरूरत है। मांसाहार शब्द बता रहा है कि हत्या करके हासिल हुआ। जो चीज हत्याके बाद हासिल की जाती है? वह शांति, क्रांति, रक्षा और स्नेहको बढ़ाने वाला हो ही नहीं सकता।

आज दुनियामें शाकाहार एक फैशन और स्नेहका आन्दोलन बन गया है। क्योंकि यह रोगप्रतिरोधक क्षमताको बढ़ाने वाला, बीमारियोंसे छुटकारा दिलाने वाला, पर्यावरणको संरक्षित करने वाला, एक पूर्ण संतुलित आहार जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है यानी कोई बीमारी इसके संतुलित सेवनसे पैदा नहीं होती है। विटामिंस, वसा, ऊर्जा, काबोहाइट्रेड, प्रोटीन, खनिज, कैल्सियम, फॉसफोरस, लोहा शाकाहारी पदार्थोंमें जितना होता है उतना मांस, मछली एवं अंडेमें नहीं मिलता, यह वैज्ञानिक तथ्यसे भी साबित हो चुका है। जितना सुपाच्य शाकाहारी आहार होता है उतना मांसाहारी नहीं। बिना किसीके हत्या किए शाकाहार, फलाहार, अन्नाहार और रसाहारको आसानीसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन मांसाहार बिना हिंसा या हत्याके हासिल ही नहीं हो सकता। पर्यावरणके लिए बूचड़खाने बेहद खतरनाक हैं। इस हकीकतको भी समझने की जरूरत है। अब तो विदेशी वैज्ञानिक, चिकित्सक और परीक्षक मानने लगे हैं कि शारीरिक एवं मानसिक सेहतके लिए जितना मुफीद शाकाहार है? उसकी तुलनामें मांसाहार नहीं है। पश्चिमके जाने-माने डाक्टर टामसन डिटनका मानना है कि फलों और सब्जियोंमें ऐसी तमाम चीजें पायी जाती हैं, जो मांस या मछलीमें नहीं होती। मिसालके तौरपर सब्जियोंमें टार्टिक एसिड, आक्जैलिक सिट्रक, ऐसटिक और मैलिक एसिड प्रमुखसे पाये जाते हैं? ये मांसमें नहीं मिलते। पश्चिमके जाने-माने प्रोफेसर बोडले नार्ड कहते हैं। हमारे भोजनमें सब्जियोंका एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। मांस वाले भोजनको छोड़कर हम बेहतर सेहतके साथ रह सकते हैं। पाचनके नजरियेसे भी शाकाहार बहुत मुफीद है। शाकाहारी हर पदार्थ ज्यादासे ज्यादा तीन घंटेमें पच जाता है जब कि मांस, चर्बी पचानेमें आंतको चार और पांच घंटे लगते हैं। इसी तरह सस्ता और हर जगह उपलब्धताके नजरियेसे भी शाकाहार मांसाहारकी अपेक्षा ज्यादा मुफीद है। इसी तरह नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नजरियेसे शाकाहारका सेवन ही सबसे बेहतर माना गया है।

प्रकृतिसे हम यदि जुड़े रहें हैं तो हमें जितना हमारा बच्चा प्रिय लगता है उतना ही खरगोश और हिरणका बच्चा भी प्रिय लगेगा। जाहिर तौरपर जो प्रिय लगता है उसकी हत्या हम करनेसे हिचकिचाते हैं। मांस खाने वालोंका तर्क होता है कि वे तो मांस खाते हैं? जानवरकी हत्या थोड़े करते है। यह तर्क देते हुए यह भूल जाते हैं कि हत्या जिसके लिए की गयी? किन कारणोंसे की गयी? इसमें जिसका भी सहयोग होता है, वे सभी जिम्मेदार हैं। प्रकृतिकी भाषामें कहें तो अपराधी हैं। यह सवाल भी अक्सर किया जाता है कि यदि जीव-जन्तुओंको इंसान न खाये तो इस धरतीपर इतने जीव-जन्तु बढ़ जायंगे कि इंसानका रहना मुश्किल हो जायगा। सामान्य रूपसे देखा जाय तो बात ठीक लगती है। लेकिन यदि ठंडे दिमागसे सोचना शुरू करें तो यह हकीकतसे बहुत दूर है। तालाबमें असंख्य मेढ़कके अंडे होते हैं? लेकिन तालाब कभी मेढ़कोंसे नहीं भरता। कौएका मांस नहीं खाया जाता, फिर भी कौए लुप्त होनेके कगारपर हैं। ये सब मिसाल इसलिए देना पड़ा कि मांसाहारको औचित्यपूर्ण ठहरानेके लिए किस-किस तरहके कुतर्क गढ़े जाते हैं। यदि कुतर्ककी जगह महज इतना सोच लें कि जिस जीवकी हत्या की गयी मांसके लिए, उस जीवका भी इस धरतीपर रहनेका उतना ही हक है जितनाकी मनुष्यका तो मांसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं लगेगा। शाकाहार दिवस मनानेका मकसद हम सभी यदि समझ पाये तो धरतीसे आहारके नामपर होने वाली हत्याएं ही बंद नहीं होंगी, बल्कि धरतीपर शांति, स्नेह और करुणाकी धाराएं बहती हुई नजर आयंगी।



फलदायी धन

❐ **सुधांशु जी महाराज**

ऋग्वेदका यह मंत्र अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवेदिवे। यशसं वीरवत्तमम्। हमें संदेश देता है कि हम ईश्वरके बनाये नियमोंसे ही धन कमायें। अनुचित रीतिसे कमाया धन हमसे दूर रहे अर्थात् धर्मसे कमायें और धर्म एवं दानमें खर्च करें। धोखा देकर, चोरी, घूसखोरी, करचोरी, भ्रष्टाचार आदिसे धन कमाना भी लोभ है। दहेज प्रथा भी लोभका ही एक रूप है। धन कमानेके ये सारे तरीके बेइमानी वाले हैं और हमारी आत्माको पतित करते हैं। हमारे वेद मनुष्यको लोभसे परे रहनेका उपदेश देते हैं। इस लोभके अनेक रूप हैं। अपने स्वास्थ्यका नाश करके धनप्राप्तिके लिए प्रयत्न करते रहना भी लोभ है। परिवार एवं बच्चोंकी उपेक्षा करते हुए धन कमानेमें लगे रहना भी लोभ है। मनुष्य इन्हींके लोभ-लालचमें पड़कर सर्वत्र निन्दनीय बनता है। यह सच है कि इस संसारमें सर्वत्र अर्थकी प्रधानता है। जीवनमें प्रत्येक कार्यके लिए धन आवश्यक है। छोटा काम हो या बड़ाए धर्म हो या राजनीति, साधना हो या अनुष्ठान सभीके लिए धनकी आवश्यकता होती है। अतएव हमारे वेदोंसे लेकर ऋषियोंतकने धन संग्रहको भी एक आवश्यक कर्तव्य बताया है, परन्तु सद्पुरुषार्थसे ही अधिकाधिक धन कमानेकी सराहना है। इससे ऐश्वर्य और श्रीवृद्धि का वरदान मिलता है। श्रीवृद्धि और सौभाग्यके लिए ज्ञान और दक्षता आवश्यक गुण हैं। दक्षता किसी विशिष्ट कार्यमें अनुभवजन्य कुशलताको कहते हैं। यह कुशलता ही समृद्धिका मार्ग प्रशस्त करती है। मनुष्य जीवनमें ईश्वरके बाद चरित्र और फिर धनका महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्यकी धनसे कभी तृप्ति नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा विकार है। लोभ मनुष्यकी बुद्धिको अज्ञानरूपी अंधकारसे ढांप देता है। उसकी बुद्धि अज्ञानसे ढक जाती है तो वह अमानवीय कर्म करनेमें भी किसी प्रकारकी लज्जा अनुभव नहीं करता। निर्लज्ज बनकर वह अपने धर्मकी हानि कर लेता है। इस प्रकार वह धन, धर्म और सुख तीनोंको नष्ट कर देता है। अनीतिपूर्वक कमाया हुआ धन मनको अशांत और बेचैन रखता है, ऐसे घर और परिवार बुरे कार्योंमें फंसकर बरबाद हो जाते हैं तथा मनुष्यताका नैतिक पतन होता ही है। इसीलिए हमारे वेद निर्देशित करते हैं कि मनुष्यको धर्मानुसार आचरण करते हुए ही पुरुषार्थ करके अधिकसे अधिक धन कमानेका प्रयास करना चाहिए। जो धन पवित्र होता है, वह सुखए शांति एवं संतोष प्रदान करता है। मनुष्य ऐसे धनको स्वयं अपनी आवश्यक आवश्यकता पूर्तिके पश्चात् शेषको समाजके उत्थानमें व्यय करके आनंदित होता है। जन-सामान्यका उस धनसे उत्कर्ष होते देखकर वह मन ही मन प्रफुल्लित भी होता है। यही पवित्र धन लोगोंमें सात्विकताका विकास करता है तथा सबको सत्याचरणमें प्रेरित करता है।

मोबाइलके प्रति बढ़ती दीवानगीने बढ़ाया अपराध

❐ **योगेंद्र**

युवा किसी भी देशका भविष्य होते हैं। देशका भविष्य बनने वाले युवा भविष्यकी चिन्ता किये बिना सिर्फ एक झूठी होड़का शिकार हों तो देशका भला कैसे होगा। मौजूदा दौरमें मोबाइलको लेकर जो मारामारी मची हुई है, उसे देखकर लगता है कि जैसे देशके युवाओंके सामने कोई चुनौती नहीं बची है। युवाओंके स्वास्थ्य और भविष्यपर मोबाइलके नयेसे नये ब्रांडोंका आकर्षण उन्हें दलदलकी तरफ धकेल रहा है। महंगे मोबाइल ब्रांडोंके जुनूनसे तो यही लगता है कि इस देशमें बेरोजगारी और युवाओंसे जुड़ी कोई समस्या बची ही नहीं है। नयेसे नये मोबाइल ब्रांडको पानेके लिए देशके युवा मारामारी करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे इतने जरूरी काममें जुटे हुए हैं कि यदि यह नहीं हुआ तो उनका भविष्य खराब हो जायगा। एक अमेरिकी कम्पनीके नये ब्रांडको लेकर युवा रातभर लाइनमें खड़े रहे और अपने नंबरका इंतजार करते रहे। दिल्लीसे मुंबईतक देशके कई शहरोंमें इस कम्पनीके स्टोरके बाहर सैकड़ों लोग सुबह स्टोर खुलनेकी इंतजारमें रातभर कतारमें लगे रहे। वह भी एक ऐसे मोबाइलके लिए जिसकी कीमत भी डेढ़से सवा तीन लाख रुपयेतक की है। इनमें चंद ही ऐसे युवा होंगे जो इतने महंगे फोनसे कुछ कमाई करेंगे, बाकी सभी तो सिर्फ जुनूनके शिकार हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोग महंगा फोन खरीदनेके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं।

बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोगोंको नया फोन, नयी कार, नया गैजेट या कोई भी लेटेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले खरीदनेकी इतनी जल्दी क्यों होती है। साइकोलॉजीमें इसे नयापन अर्थात् अनोखा या अलग अनुभव करनेकी इच्छा कहते हैं। इसे आकर्षणसे जोड़कर देखा जाता है। इनसानको नयी और अलग चीजें स